aware of the News item published in the Times of India.

(b) and (c) The State Government is seized of the problem and has taken progressive remedial measures and monitoring in the light of the recommendations of the Fact Finding Committee set up by them in October, 1982.

SHRI SAROJ KHAPARDE: Mr. Chairman, Sir, I am very happy to know that the Government is aware of the news that appeared in the Times of India. But after seeing the reply of the Minister, I am, indeed, not very happy, because this reply is not up to the mark, I can say. Sir, I would just like to know from the hon. Minister whether the State Government's report on the Totla Doh Darn Project mentions about seepage at the rate of 500 mtrs. per minute from the dam reservoir during the rains when in the year 1987-88, it was at the level of 430 mtrs. The report mentions about the seepage during rainfall in the attachment area. It implies that during very heavy rains in the catchr ment area, the seepage or the leakage would be endangering the safety of the dam. I would just like to know from the hon. Minister whether it is a fact that while planning the dam area, it was regarded as an earth-quake-free zone. But in the year 1957 and in the year 1982, there were two earthquakes at a site 10 kms. away from the dam and an earthquake closer to the dam could result in a crack to the dam. Therefore, what steps do the Government propose to take to ensure the safety of the project in this regard?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: When this dam was being planned, the Government Was aware that the. geological formation in the area was given to seepage and they had, therefore, requested the Geological Survey of India to send one of their experts to be associated with the planning of the dan. The fact-finding committee appointerA by the Maharashtra Government had reported that while planning the dam, the opinion of the Geological Survey of India was fully taken into account and accordingly the design of the dam was formu lated. The question of seepage that has been raised by the hon. Member also engaged the attention of the fact finding committee. The maximum seepage that the hon. Member was re ferring to in the year 1986-87 was 8.09 litres per second and this was ob served by the Committee as well as by the Government. An impervious blanket in the upper-stream was done and the physical stability of the hills nearby was also ensured. Now the maximum seepage noticed in 1991, that is this year, —we have got the report of that—is around 9.90 litres per second. Now the corrective measures that have been taken mainly in the dam which is a masonry dam have now controlled the seepage and I can assure the hon. House and the Member that there is absolutely no danger to the towns of Nagpur or Kanki or anywhere else because of this dam. As far as the seismic problems are concerned, it is a fact that two seismic quakes were felt near the dam but the design was made in such a manner that the reservoir competency and the seismic resistance design were built in this dam. Therefore, the Member can be assured that there would be on such problem in future from this dam either from seepage or from seismic shock.

World Bank Observations regarding Agricultural growth in the country

23. SHRIMATI KAMLA SlNHA:†
SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Bank, in its report has made certain observations regarding growth of agriculture in the country arid have made some suggestions for revi-

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kamala Sinha.

sing the agricultural policy and strategy to overcome constraints in its growth;

(b) if so, what are the salient features of the report; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. A Country Economic Memorandum captioned Agriculture—Challenges and opportunities' covering some of the aspects of agriculture in India was prepared by World Bank in August, 1991.

(b) Some of the main recommendations concerning the agriculture sector relate to increasing overall allocations for agriculture, selective opening up of agriculture sector to the world markets, improving the effcien-t-y of agricultural investments, rationalising subsidies and argeting them towards deserving people, diversification of agriculture to meet the growing demands, providing better incentives to farmers for crop production and revitalisation of rural banking. The Report advocates integration of Indian agriculture to the rest of the World agriculture economy and places major emphasis on market factor for promoting investments in agriculture.

(c) Some of the recommendations of the Report relating to improving the efficiency of agricultural investments are consistent with the Government of India's policies on agricul-ture. However, integration of Indian agriculture to the rest of the World Agricultural Economy has to be selective and reciprocal. Similarly, while markets and privatisation have their role, there are certain limitations in their functioning in India agriculture) particularly in the case of rain-ftf agriculture.

श्रीमती कमला सिन्हा : सर, सरकार का जो जवाब आया है और मैंने जो प्रश्न पूछा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है । मैंने यह पूछा था कि वर्ल्ड बैंक का जो सेप्टेम्बर महीने में 1991 का रिपोर्ट आया है वाल्यूम 2 उसमें उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है फार रिवाइजिंग एग्रीकल्चर पालिसी एण्ड स्ट्रेटेजी टू ओवरकम कन्स्ट्रेंट्स इन इट्स ग्रोथ । तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट का कुछ हिस्सा बता दिया कि क्या क्या रिपोर्ट में है । इसमें उन्होंने एक तो कहा कि "प्राइवेटाइजेशन एज ए गाइडिंग फैक्टर फार प्रोमोटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन एग्रीकल्चर" और वर्ल्ड मार्केट के साथ तालमेल करके चलाने के लिए क्या करना होगा उसके बारे में बताया । लेकिन जो सैलिएंट फीचर्स थे इस रिपोर्ट के उनके बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा । मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि हमारे देश में कृषि विकास के लिए पहले तो कृषि का विकास होगा तभी हम वर्ल्ड मार्केट में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर्स एकानामी को आप आगे बढ़ा सकते हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या इन्होंने वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, जो सुझाव आए हैं उसके मुताबिक वाटर मैनेजमेंट के बारे में कोई दिशा निश्चित की है ? निश्चित इरीगेशन कितनी जमीन में होती है, क्योंकि जहां तक हम लोगों की जानकारी है आज जितनी हमारी इरीगेटेड लैंड है पूरे देश भर में वह केवल पांचवां हिस्सा ही इरीगेटेड है, बाकी बरसात के ऊपर ही निर्भर करती है । तो जब तक निश्चित सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, हमारी कृषि बढ़ नहीं सकती है और पिछले दिनों इसीलिए एग्रीकल्चरल ट्रेड भी हमारा गिरा है पिछले दशक में केवल आज 18 परसेंट है, तो वाटर मैनेजमेंट के बारे में सरकार का क्या कहना है ? दूसरी बात यह जो कृषि के ऊपर जो इतना कृषि, एग्रीकल्चरल ट्रेड की जो संभावना है उसके बारे में सरकार कौन सा

निश्चित दिशानिर्देश कर रही है यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : माननीय सभापति महोदय, सवाल का पूरा जवाब उसमें दिया गया है । यह एक आर्थिक रिपोर्ट थी। खास तौर पर यह जो सुझाव दिए गए वह थोड़े से हिस्से के कृषि के दिए गए हैं । जो मुद्दे कृषि के थे उन सभी को उन्होंने हाथ नहीं लगाया और न ही उस बारे में उन्होंने सोचा । जैसे आपने फर्माया कि वर्षा आधारित हमारी खेती है उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया उसको देखा ही नहीं, उसी तरीके से उन्होंने पशुपालन को नहीं देखा, इसी प्रकार से उन्होंने उद्यान विभाग को नहीं देखा, मछली को नहीं देखा, किसी प्रकार से नहीं, यह तो जैसे इकोनोमिक सर्वे किया था, उसमें कुछ सुझाव दिए थे । वह हम देखे हैं । जो आपने कहा कि हम इसको खोल दें ट्रेड के लिए, बाहर के लिए, तो यह तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है यह रेसीप्रोकल है । एक हाथ से नहीं, यह तो दोनों हाथों से ताली बजती है । टू लेन ट्रैफिक होगा तभी बात बनेगी, जब वे हमारे साथ रेसीप्रोसिटी करेंगे उस वक्त आएगा तो हम देखेंगे । उनका बंद रहे और हम खोल दें इस प्रकार की बात यहां चलने वाली नहीं है और जो सुझाव है आपके हिसाब से ठीक है हम उनको देखते हैं, यह तो सुझाव हैं पालिसी से उनका कोई मतलब नहीं है ।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के जो रेव्यू आए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या-क्या आगे करना चाहिए, उसमें जो उनके आपरेटिव पोर्शन्ज हैं वह यह हैं कि :

Major efforts are needed in four key areas firstly forging a coherent agricultural policy.

जिसके बारे में मैंने मंत्री जी से अभी पूछा था । मंत्री जी ने साफ उसका कहा कि इसके बारे में उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया । दूसरी बात रिपोर्ट में कही :

Setting investment priorities and regaining control of public expenditure.

Improving systems of productivity and assuring substantiality.

Building institutional capacity in both the public and private sectors to manage irrigation more efficiently and effectively.

उसके बाद लास्टली उन्होंने कहा :

There is scope for harnessing tremendous energy and capital, both human and investment.

प्राइवेट सैक्टर भी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी ।

What important role Government has to play in this regard, specially, in implementing irrigation?

तो जो मेजर थ्रस्ट उनका वही था वाटर मैनेजमेंट एंड इरीगेशन है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना हैं ?

श्री बलराम जाखड़ : कृषि का मेन आधार सिंचाई है, वैसे भी देश में आज जो स्थिति है वह यह है कि 30 प्रतिशत हम सिंचाई करते है जिसको कि हम कहते हैं कि बिल्कुल सावधान तरीके और 70 प्रतिशत वर्षा आधारित है । तो उसके लिए पैसे की भी आवश्यकता है, नए डैम बनाने की आवश्यकता है, जैसे नर्मदा सागर डैम बन रहा है या और हमारे डैम बन रहे हैं उसके हिसाब से और फिर पानी का सदुपयोग करने के लिए ताकि कम पानी से ज्यादा सिंचाई हो, इस प्रकार का प्रकरण हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें फव्वारे की खेती आती है । उसमें बूंद-बूंद करके पानी आता है जिसको ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं, वह आता है । उसको करने का भी

है और खाले और नाले तथा चैनल पक्के करने का है जिससे पानी खराब नहीं हो, काम थोड़ा जल्दी चले। वह सारी बातें उसमें आधारित हैं और हम करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा दूसरे तरीके से व्यापार की बात आप जो कह रहे हैं और जो ज्यादा पैसे की बात करें वगैर पैसे के खेती है ही नहीं। आज आप पैसा लगाओ तो खेती होती है और वह हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है। जितना पैसा लगाएं खेती में अच्छा है चाहे वह प्राइवेट हो या दूसरा भी हो। अब पैसा लगाने की जहां तक बात है, हमें एक आघात पहुंचा और उस आघात से हम अभी निकले नहीं है क्योंकि हमारी जो ऋण नीति थी, उस ऋण नीति को तबाह कर दिया गया है। वह सबसे ज्यादा घायल हो गयी है। उसमें लोगों का विश्वास उठ गया है। बैंक की हालत पतली हो गयी है। सोचे-समझे वगैर जो काम किया जाता है, उसका नतीजा यही होता है कि, "नीम हकीम खतरा-ए जान।" तो उस हिसाब से निकलने की हमें जरुरत है और मैं दोबारा ऋण नीति के हिसाब से उन संस्थाओं को मजबूत करना चाहता हूं। जो ऋण देने वाले हैं, जैसे कोआपरेटिव्स के हैं या दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, लोग जिन्होंने पैसा लिया और जिनका थोड़ा-बहुत माफ हो गया और जिनका नहीं हुआ था तो वह सोचते हैं कि अगली दफा कोई माफ कर देगा। यह एक किस्म की अविश्वसनीयता आ गयी है सारे सिस्टम में और ऋण देना भी और दूसरा प्राइवेट पैसा लगाना भी अत्यावश्यक है ताकि खेती आगे बढ़ सके। यह सारी बातें हमारे बीच में हैं और जो अच्छी बात होती है, वह हम ले लेते हैं। सजेशन जो अच्छा होगा जैसे कि हिंदी का एक दोहा है, "उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि अधम पर होय, परौ अपावन ठौर में कंचन तजत न कोय।" तो हम सोना उठाने के पक्ष में हैं। दूसरी बात हम लेने के पक्ष में नहीं हैं।

श्री सभापति : जनाब मोहम्मद अफ़जल।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति जी...

श्री सभापति : आपने दो पूछ लिए।

श्रीमती कमला सिन्हा : एक और पूछना चाहती हूं।

श्री सभापति : नहीं दो हो गए। आपके नीचे जो बैठे हैं, उन्हें बता दीजिए। आपको जो पूछवाना है, उनसे पूछवा लीजिए।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल: महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि किसानों को दस-दस हजार रुपए के कुछ कर्जे दिए गए थे। इस सिलसिले में आज तक यह पता नहीं लग पाया है सही तरीके से कि वह कर्जे माफ कर दिए गए हैं या उनसे वापिस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत से किसानों को नोटिस दिए गए और यहां तक कि कुछ किसान बेचारे घर छोड़कर भाग गए क्योंकि उनको बहुत परेशान किया गया। दूसरे, जहां विकास की बात आपने की और बताया कि स्थिति काफी तबाह हो गयी है तो स्थिति को सुधारने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया है और जो सबसिडी दी जाती थी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसमें जो कमी की गयी है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी करने की आपकी कोई स्कीम है ताकि उससे किसानों को कुछ फायदा हो सके।

श्री बलराम जाखड़: श्रीमन् वही तो सारी बात करता रहा। सारी रात मैं बात करता रहा और सुबह आपने कहा कि सोए थे कि नहीं सोए थे। ऋण की बात तो मैं कर रहा था कि उसी ऋण ने तो तबाह किया है। उसी पालिसी ने तो सत्यानाश किया है। इससे ज्यादा नुकसान किसान का आज तक कभी नहीं हुआ।

दूसरी बात, जितना हो सकता है, कृषि को उन्नत बनाने के लिए जो भी योग्य साधन या नीतियां बनायी जा

सकती हैं, वह बनायी जा रही हैं और उसके हिसाब से पूरा करने की इच्छा है वह हम करना चाहते हैं और करेंगे ।

SHRI A. G. KULKARNI; Sir, I thought that the hon. Minister was himself was a leader of the farming com munity, but after the statement that he has placed on the Table of the House, particularly in relation to the conditions prevailing in this country, I am doubtful about it now. During the last two to three years the agricul tural policy in particular has been distorted and there is a doubt whe ther the farmers themselves are trea ted as equal citizens. Sir, while the contribution of the farming community to the GNP was 50 per cent, the investment in this sector was only 21.8 pes- cent and out of this on education and health of rural people they have spent only 5.2 per cent. While giving this reply, he might have taken all these factors into consideration and, therefore, I would like to know whe ther there is a proposal to increase the investrment in the agricultural sector. Unless that is done, the total agricul tural production will hot increase. You also promised in the last session that a document on agricultural policy will be placed on the Table. When are you going to do that? Now I find that the crop is ready. Again the new crop will be there. Now, Wheat production has risen by 74 per cent while in real terms, the support price has come down by 44 per cent. You yourself are a leader of the farming community. How are you supporting such policies? I don't believe in this document at all. I believe in my Government and the farmer of this country. So, would you please enlighten us as to what is really being done except lip sympthay because the intellectuals and urbanites are not interested in agriculture?

SHRI BALRAM JAKHAR; Sir, the honourable Member's observations deserve all the attention and I think I will give all the attention to them— and I Understand the feelings inherent in what he has expressed. I know that without investment there can be no good agriculture nowadays; it cannot be remunerative, it cannot be productive. It has to be so and we want investment. But what are the resources at our command at this time? I am trying to wrest as much as possible for agriculture. Let us see what we can get next time for that. As an example, I can say that so far. in horticulture there has been an investment of about Rs. 16 crores only in the last year or so. But what is Rs. 16 crores for horticulture whereas in the world markets people produce and process 50 to 60 per cent as processed foods and we do only a small fraction of it? Therefore, I am demanding much more than that, so much that it cannot be easy: it is a mind-boggling sum. But will they give it to me? I will try my best. I am going to have that infrastructure laid down in the coming years, because on that lies the prosperity- of this country and the prosperity of the farmer.

I say that the policy so far has been to sustain agriculture to sustain the availability of food for the people. But I don't want it that way. I want prosperity for the farmers and, as you have said, I want them to rub shoulders with the highest and to have equal status in life. I don't want to depend upon anything else and 1 will see that something is done regarding that—and I will need all your support for that.

SHRI A. *G.* KUUKARNf: Sir, I only want to draw his attention to the wheat production which the farmer has raised while, ill real terms, you are suppressiag the support price. There is no money for tractors. What infrastructure do you desire to have?

SHRI BALRAM JAKHAR: I will do that; I know that, Sir. I want to have some soft of a policy which ensures proper remunerative price to the farmers. I want to tag it along with the consumer index as it is done in other walks of life so that when the index goes up they get increased and when it comes down they can be

reduced. I was just piking to the honourable Member here from Punjab, Jagjit Singhji, that we must find some sort of a solution which should be a permanent solution and not ad hoc adjustments time and again. But I know that there is a limit and just in one jump I can't do it because then all the House will be upset and people will say that inflationary trends come because of the farmer. The farmer is at the receiving end—that is what they say. They do not realize what farming means. If I were to send them on a cold winter night in December, when the cold wind is blowing from the mountains, and ask them to irrigate the fields, then they will realize what it means to be a farmer. That is what I am trying to tell. Come with me and see what it means to be a farmer.

MR CHAIRMAN: You take the whole House!

SHRI BALRAM JAKHAR: Thats right, Sir. I will take you all, Sir. ... *(.Interruptions)...* And my worry will be to safeguard you all from pneumonia!

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, the statement laid on the Table of the House by the honourable Minister is more concealing the truth than reveal. ing *the* truth. For example. *The Economic Times* has recently published, what they call, the executive summary of the Report of the World Bank. This is a crucial item—and I read it from *The Economic Times:*

> "Policy changes are also needed to encourage more private research."

That is okay.

> "For example, through protection of intellectual rights on the immediate relaxation of control on technology inputs"

Sir, here is the time bomb. The plant breeder's right is protected under the intellectual property rights. That means, Sir, we are entering into the era of Green Revolution by developing hybrid seeds in our universities—and the honourable Minister is an expert in that area. In his State. in Punjab, Haryana and other States, we have been doing that. If you subscribe to this view and if you follow the plant-breeder's rights according to the intellectual property rights, you have to pay a huge sum of money to the multinationals who develop new varieties. We cannot develop new varieties. It will hinder our growth, and we cannot, through selection or through genetic engineering, enter upon that field. Then we will be at the mercy of the multinationals. We have to pay for developing seeds, and even for selling the seeds to the farmers we have to pay a huge amount So. I want to know whether what has appeared in thus paragraph in "The Economic *Times"* is a true statement and if so, what the reaction of the hon. Minister is. Are we going to bind ourselves to the plant-breeder's rights and dissipate whatever we have gained by the Green Revolution?

SHRI BALRAM JAKHAR: sir, they are suggestions. They have done an economic survey. We accept what is beneficial to us. I cannot barter away the freedom and the rights 61 my plant-breeders. I have got ray own scientists. I have full faith in them. I want to have major breakthroughs in times to come We have been able to have some breakthrough?. As far as oil-seeds production is concerned, I can say that from 10.7 million tonnes we have reached 19 million tonnes. In two years' time we are going to be self-reliant in oilseeds production, in edible oils also. That is why I want to safeguard them. Don't worry about it. *I* will say that it is a two-way traffic: it is not a one-way traffic. I am not going to barter away the rights of my farmers.

SHRI MURASOLI MARAN: My question is: Are you going to subscribe to the plant-breeder's rights etc.?

SHRI BALRAM JAKHAR: I am not going to barter away the interests of the farmers of the country.

MR. CHAIRMAN: He will not do it.

SHRI N. E. BALARAM: He will not do it. But the pressure is there. That is the point.

श्री भुपेन्द्र सिंह मान : सभापति जी सवाल में पूछा गया है कि रिवाइजिंग द एग्रीकल्चर पालिसी, इसका मतलब यह है कि कोई एग्रीकल्चर पालिसी है ? मेरी जानकारी के अनुसार इस देश में अभी तक एग्रीकल्चर पालिसी बनी ही नहीं । अगर बनी नहीं तो किस वजह से नहीं बनी है ? अगर बनी है तो जो जवाब दिया गया है उसमें इसका मेंशन क्यों नहीं किया गया कि कोई एग्रीकल्चर पालिसी है और उसको रिवाइज करने की कोई बात चल रही है ? इसके साथ-साथ जब मंत्री जी ने खुद कहा है कि प्राइस डेक्स या जो पेरिटी प्राइस है, उसके मुताबिक किसान को दाम नहीं मिल रहा । तो उसके ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उसमें किसान का क्या दोष है ? और, उसका दोष न होते हुए कर्जे राइट-आफ करने की बात होती है तो उसमें शासन को क्या दिक्कत होती है ? अगर किसान के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं तो उसमें सरकार का ही दोष है । सरकार को इसको मान लेना चाहिए कि जो कर्जे दिए हैं वह रिमुनेरेटिव नहीं थे, उससे किसान की हालत नहीं सुधर सकती थी, उसमें उसकी रोजी-रोटी नहीं बन सकती थी और इसलिए उसके ऊपर कर्जे चढ़े हैं । इन कर्जों के बारे में यह कहना कि इसे राइट-आफ करने से कोई बहुत बड़ा देश का नुकसान हो गया, यह उचित नहीं बल्कि कहना होगा कि यह अच्छी बात हुई है और इसको बढ़ावा देने के लिए जो पीछे गलतियां की गई हैं उनको ठीक करने की बात होनी चाहिए । इसके साथ ही पेरिडी-प्राइस की बात हो ताकि रियल टर्म में किसान को कुछ मिले । तो इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ? यह तीन मेरे सवाल हैं, जिनके बारे में मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहता

श्री बलराम जाखड़ : सभापति जी, कृषि के मुतअल्लिक था, पिछली दफा एक पेपर तैयार किया गया था । वह मैंने तैयार किया गया था । वह मैंने सब स्टेट्स को भेज रखा है । अभी दुबारा मैंने रिमाइंडर भी भेजा है ।

श्री सभापति : उनकी राय जानने के लिए ?

श्री बलराम जाखड़ : जी हां, उनकी राय जानने के लिए । अभी मैंने दुबारा कहा है कि जल्दी राय भेज दीजिए, जिससे कि हम इनका निर्धारण कर सकें, देख सकें कि क्या करना है । अभी तक सबा नहीं आया है, कुछ का आया है । बाकियों का मैं इंतजार कर रहा हूं ।

आपने दूसरा सवाल किया था कर्जे का । किसान का ऋण-मुक्ति से कल्याण नहीं होता है । उसको सब प्रकार से देखना है । उसके घर में पैसा आता रहा । एक दफा दो हजार, चार हजार से गंगा तर गए तो वह हमारा कल्याण नहीं होगा भगवन् । यह तो फिजूल की बात है । इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है । मैं इस बात को मानता हूं अगर नहीं पैसा हम किसान के हित में लगा देते और उसके लिए शाश्वत काम कर देते तब बात बनती हमारी ।

तीसरी बात आपकी रह गई पेरिडी की । उसके मुतअल्लिक थे एक, दो, चार महीने में अभी कुछ नहीं कर सकता, न किया है । हम विचार कर रहे हैं और उसके हिसाब से समझेंगे कि कैसे इसको करेंगे । इसमें आपकी भी सहायता लूंगा और सब मेरे मेम्बरान साहबान जो हैं इन सबकी सहायता से सारा कार्य कर पाऊंगा ।

हम ऐसा फार्मूला बना सकें जो सबको संतुष्ट कर सके, वह मैं चाहूंगा ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जब कहा कि वह सोना लेंगे और यह नहीं लेंगे, क्षीर-नीर का काम करेंगे, तो अच्छी बात है । लेकिन मंत्री महोदय के कहने और सरकार के

करने, दोनों में बड़ा फ़र्क है। हम लोगों को फारेन कम्पनी का, पैप्सी कोला का पोटेटो चिप्स हर जगह खाने को मिलता है। तो वह तो खेती में आता है। क्या हमारे किसान पोटेटो चिप्स नहीं बना सकते थे और हमारे देश के लोग नहीं बना सकते हैं? इसलिए आपकी कथनी में और सरकार की करनी में बड़ा फर्क है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : तो पहला प्रश्न तो यही हुआ कि इनकी कथनी-करनी में बड़ा फर्क है।

श्री सभापति : यह फूड प्रोसेसिंग तो दूसरी मिनिस्ट्री के अंडर है।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, नहीं। वह भी वही है, कृषि के संबंध में है।

श्री संघ प्रिय गौतम : ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी है सर।

श्री सभापति : क्वेश्चन आवर में ज्वाइंट डिस्कशन....

श्री चतुरानन मिश्र : जो खतरा उत्पन्न हो गया है, जैसे कि मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि जो खेती है भारत की, उसको वर्ल्ड आई०आर०आई० के साथ इंटिग्रेशन करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसके मुतल्लिक सरकार को सफाई पेश करनी चाहिए कि जो "गाट्स" में या दूसरी जगह दबाव डाल रहे हैं कि पेटेन्ट लाल में आप ऐसा संशोधन कर दीजिए ताकि उनको सीधा यहां आना पड़े, हमारा अपना अनुसंधान चौपट हो जाएगा। इसलिए वह इसको कहें कि हम इसको किसी हालत में नहीं मानेंगे, अपने अनुसंधान पर किसी तरह की चोट नहीं आएगी।

श्री सभापति : वह आपकी राय से सहमत हैं। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : वही हमने कहा कि वह इसको डिक्लेअर कर दें कि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि "गाट्स" में रोज हम लोग देख रहे हैं और आप जानते हैं कि अभी....

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हम पूछ रहे हैं।

हम दूसरा यह चाहते हैं कि जो लघु और सीमान्त किसान हैं उनको जब तक सस्ते दाम पर बिजली और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक उनके पास ऐसा मार्किटिंग सरप्लस नहीं है, तो विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, बल्कि उल्टा प्रावधान है। आपने ठीक ही कहा कि जो लोग बेचेंगे, उनको उचित दाम दिया जाए। वह ठीक है और उसका हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन जो गरीब किसान हैं उनके बारे में हम आपसे कहेंगे कि उनके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उनके बारे में हमारी सरकार क्या सोच रही है?

MR. CHAIRMAN: That is correct.

श्री चतुरानन मिश्र : बीज के बारे में बात आई है। अभी हमारे पास जो सूचना प्राप्त है, उसके मुताबिक वह मांग करते हैं कि बराबर बीज वही सप्लाई करेंगे। हमारे किसान अगर उपज पैदा कर लेंगे तो उससे बीज नहीं बना सकते हैं, यह उनकी मांग है। इसलिए इंटिग्रेशन में इसको नहीं स्वीकार करेंगे, यह भी सरकार स्पष्ट करे।

श्री बलराम जाखड़ : महोदय, उन्होंने कहा कि कि कथनी और करनी में अंतर है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि "अंकल चिप्स" का इसके साथ क्या संबंध है। आप "दादा चिप्स" बनाइए, कोई रोके तो मैं देखता हूं, कैसे रोकेगा।

श्री चतुरानन मिश्र : आप अगर विदेश वाले को मंगा देंगे तो हम बेचेंगे क्या?

श्री बलराम जाखड़ : आप करने में सक्षम बनिए, आप करिए, कौन रोकेगा, । मैं तो कृषि को उद्योग-आधारित बनाना चाहता हूं। हम अपनी कृषि को जब तक उद्योग-आधारित नहीं बनाएंगे, तो एक-एक, दो-दो एकड़ में आप समृद्धि नहीं ला सकते हैं । तीन प्रतिशत लोग बाहर खेती करते हैं या सत्तर प्रतिशत करते हैं, जमीन रबड़ तो है नहीं जो बढ़ जाएगी । जमीन तो उतनी ही है, भगवान ने एक ही बार बनाई है सारे संसार में.....

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं जमीन...

श्री सभापति : वह आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़ : मेरी बात तो सुनिए । उसके साथ संबंधित है, मैं कृषि की बात कर रहा हूं कि अगर हम कृषि को उद्योगों के आधार पर परिवर्तित नहीं करेंगे तो कैसे हम समृद्धि लाएंगे ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप भी बनाएं, अपनों को प्रोत्साहन दीजिए और मैं भी चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हम अपनों को बढ़ावा दें और कोआपरेटिव सैक्टर में, गांवों में कृषि पर आधारित उद्योग लगें जिसमें फलों का उत्पादन हो, उनमें प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो और उसी हिसाब से अच्छी फसलें, जो कि ज्यादा पैसा उसको दे सकती है, उन पर विचार करके हम उनको समृद्ध-शाली बनाना चाहते हैं । बीज जो बनाना है, वह हमारे साइन्टिस्ट्स के मार्फत बनवाना है और साइन्टिस्ट्स ने जो अन्वेशन करना है, उनके आधार पर आज तक देश रहा है और आगे भी रहेगा । अगर कुछ अच्छा होगा तो दोनों हाथों से ताली बजेगी । हमें कुछ फायदा होगा तो हम उनसे ले लेंगे, उनको कुछ फायदा होगा तो हमसे ले लेंगे । एक तरफ फायदे वाली बात मैं नहीं मानने वाला ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, लघु-सीमान्त किसानों के बारे में...

श्री बलराम जाखड़ : लघु-सीमान्त किसानों का पहले भी ध्यान रख चुके हैं, उतना पैसा हमने ज्यादा नहीं था, जितना पैसा था—405 करोड़ रुपए, वह पहले ही हमने उनके लिए छोड़ दिया था ।

[The questioner {Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare and Shri Be-kal Utsahi) were absent. For answer vide c.ol. 34-35 *infra]*

नया लघु इस्पात निर्माण संयंत्र

†*25. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री रणजीत सिंह :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 1991 में लघु इस्पात निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई दिशा निर्देश घोषित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तब से लेकर कितनी लघु इकाइयों ने अपने आवेदन पत्र सरकार को प्रस्तुत किए हैं;

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी गयी है, और

(घ) यदि हां, तो इन इकाइयों को कहां-कहां लगाने का प्रस्ताव है और उनमें से प्रत्येक की निर्माण क्षमता क्या होगी और उनमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV); (a) The Government did not announce any guidelines for setting up of ministeel manufgesturing plants in july, 199:1 • However, the new Industrial policy was announced in July, 1991 and this exempts the iron and steel industry (including ministeel plants) from the provisions of compulsory licensing subject to lacational restrictions. En-trepreneurs have to only file an Indus-trial Entrepreneur Memorandum with the Government.

(b) No application for industrial licence for setting up a mini steel plant

† सभा में यह प्रश्न सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा द्वारा पूछा गया ।